

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरठ-लखनऊ समेत तीन नई वंदे भारत एक्सप्रस रेलगाड़ियों को दिखाई हरी झंडी।
2. उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से हुई सम्पन्न।
3. लखनऊ हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिये तत्काल कदम उठाने के दिये निर्देश।

और

4. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का करेंगे लोकार्पण : गोरखपुर में 49 एकड़ में 176 करोड़ रुपये से अधिक लागत से बना है स्कूल।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीन वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़िया हैं – मेरठ से लखनऊ, मदुरै से बंगलुरु और चेन्नई से नागरकोइल। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि वंदेभारत रेलगाड़ियों के विस्तार से देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा रहा है। उन्होंने कहा कि वंदेभारत आधुनिक भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। बाइट.....

आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक के सभी लोगों को आरामदेह यात्रा की गारंटी देने तक अपना कार्य करती रहेगी।

लखनऊ—मेरठ के बीच उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से वंदे भारत ट्रेन मंगलवार को छोड़कर पूरे हफ्ते चलेगी। वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से दोपहर दो बजकर पैंतालिस मिनट पर रवाना होगी और सवा सात घंटे में रात दस बजे मेरठ पहुंचेगी। लखनऊ से चलने के बाद यह ट्रेन बरेली और मुरादाबाद में रुकेगी। मेरठ से यह ट्रेन सुबह छः बजकर पैंतीस मिनट पर रवाना होगी। मेरठ सिटी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने से विद्यार्थियों, व्यापारियों और अधिकारियों सभी को लाभ होगा। बाइट.....

आज का जो दिन है बहुत ऐतिहासिक दिन है। मेरठ कैंट क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिये बहुत ही सुविधाजनक कार्य हुआ है। नौचंदी एक्सप्रेस जो भी वो सहारपुर से चलने लगी। यहां के लिये उसका महत्व कम हो गया है। इसलिये वंदे भारत का चलना बहुत जरूरी था। माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री उनको बहुत-बहुत आभार है हमारा, क्योंकि मेरठ से और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हैं यहां से बहुत सारे लोग रोज आते जाते हैं विद्यार्थी आते जाते हैं, अधिकारी आते हैं, व्यापारी आते, तो सभी के लिये बहुत सुविधा हो गया है और इससे यहां के क्षेत्र के विकास की जो गति है वो और तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिये पांच चरणों में हुई लिखित परीक्षा आज सम्पन्न हो गई। परीक्षा के लिये 67 जिलों में कुल एक हजार 174 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे। यह परीक्षा 23 24 और 25 अगस्त फिर 30 और 31 अगस्त को दो पालियों में सम्पन्न हुई। परीक्षा में हिस्सा लेने के लिये विभिन्न प्रदेशों से अभ्यर्थी पहुंचे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये रोडवेज बसों में एडमिट कार्ड दिखा कर निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर के केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि यह देश और दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा है और हम इसे शुचितापूर्वक आयोजित करने में सफल रहे हं। उन्होंने कहा कि आने वाले एक

साल में पुलिस विभाग कुल एक लाख लोगों की भर्ती करेगा। बाइट.....

देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सह सक्षम कराने में हम लोग सफल हुए हैं और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी परीक्षा शुचिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिये जाये, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27 हजार 713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-एटीआरई कराने के लिये तत्काल कदम उठाये। न्यायालय ने कहा है कि यदि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा न हो, तो एटीआरई कराने का निर्णय दो माह के भीतर लिया जाये। साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाय, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने

अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए कल पारित किया।

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का गोरखपुर में लोकार्पण करेंगे। इसके लिए 7 सितंबर की तारीख संभावित है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। लोकार्पण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक गोरखपुर का सैनिक स्कूल खाद कारखाना परिसर में आवंटित 49 एकड़ भूमि पर बना है। 176 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले इस स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई 2021 को किया था।

केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। केंद्रीय राज्यमंत्री ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में कहा कि पीलीभीत के विकास के लिए वह संकल्पित हैं और जिले का विकास कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। श्री प्रसाद कल नवीन मंडी समिति में आयोजित आशा सम्मेलन को बोधित करेंगे और पीलीभीत मैलानी रेलखंड पर ट्रेन संचालन का शुभारंभ करेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर आठ मंडल के 28 चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राहत आयुक्त के मुताबिक, 13 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, के खिलाफ निलंबन, जवाब-तलब और अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। वहीं एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी को पद से हटाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी से लापरवाही पर जवाब तलब किया गया है। इसी तरह एक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, एक सहायक चकबंदी अधिकारी का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अलावा तीन सहायक चकबंदी

अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी। इतना ही नहीं एक सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा सेवाकाल में अनियमितता पर पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसके अलावा कई अन्य के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है।

पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में उपाध्यक्ष के दो पदों पर मिर्जापुर के सोहनलाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आयोग में 24 सदस्यों को भी मनोनीत किया गया है। इस संबंध में शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग—एक ने आदेश जारी कर दिया है। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 1 वर्ष का होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित कराने के लिये फिर से सर्वे कराया जा रहा है। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने योजना से वंचित लोगों से सर्वे में भाग लेकर पंजीकरण कराने की अपील की है। बाइट.....

गांव-गांव में हमारे सेक्रेटरी और हमारे प्रधानमंत्री आवास विहीन परिवारों का सर्वे कर रहे हैं और ये योजना बिल्कुल निशुल्क है। इसके लिये कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई अगर आपसे पैसे की मांग करता है तो आपको बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। आपका नाम अगर सम्मिलित नहीं कर रहे हैं आपके प्रधान सेक्रेटरी अपने संबंधित वीडियो से आप सम्पर्क कर सूचित करिये, उनको साथ ही साथ पीडीडीआरडीए जो आपके संचालक हैं उनको आप सम्पर्क करके 9454465284 इस नम्बर पर सूचित कर सकते हैं।

मंकी पॉक्स के अलर्ट को देखते हुए अलीगढ़ के दीन दयाल अस्पताल में एक वार्ड को आरक्षित कर दिया गया है। सीएमओ डॉ० नीरज त्यागी ने बताया कि विदेशों से जिले में आने वाले हर व्यक्ति पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर रखेगी और संदेह की स्थिति में सैम्पल लेकर जांच की जायेगी।

आज 73वां विमुक्त जाति दिवस मनाया जा रहा है। विमुक्त एवं घुमंतू जातियों से संबंधित इस दिवस का मनाने का उद्देश्य इन जातियों को मुख्य धारा से जोड़कर इनका विकास करना है। इस अवसर पर आज लखनऊ में समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने विमुक्त जातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में विमुक्त जातियों से संबंधित विकास योजनाओं और विमुक्त जाति के महापुरुषों के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं मऊ

में प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री राजभर ने कहा कि प्रदेश में 26 प्रमुख जातियां विमुक्त जातियों में शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने इनसे संबंधित एक सर्वे कराने का फैसला लिया है, जिससे इन जाति के लोगों का सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक आकलन हो सके।

(समाप्त)